3

नरसिंहपुर में किसानों का चक्का जाम

5

महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख नाम

6

सिरपुर जिले को मिलेगी करोड़ों की सौगात

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 39 प्रति सोमवार, 02 फरवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

एसआईटी जांच से भोपाल की राजनीति में हलचल, महापौर मालती राय से जुड़े आरोपों ने बढ़ाई सियासी बेचैनी

जांच के घेरे में जनप्रतिनिधि, असलम कुरैशी मामले ने उजागर किए सत्ता–संरक्षण के सवाल

कवर स्टोरी

-विजया पाटक
एडिटर

गौवंश हत्या से जुड़े एक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की सक्रियता के बाद राजधानी भोपाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी असलम कुरैशी के एसआईटी की हिरासत में जाने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस जांच के दौरान कई प्रभावशाली नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों और रसूखदार लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर सबसे अधिक चर्चा भोपाल की महापौर मालती राय को लेकर हो रही है। विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गौवंश से जुड़े इस अवैध नेटवर्क में नगर निगम स्तर पर संरक्षण दिया गया और कथित रूप से आर्थिक लेन-देन भी हुआ। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है।

आरोपों के केंद्र में महापौर, जांच एजेंसियों की निगाहें दस्तावेजों पर

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी अब उन फाइलों, अनुमतियों और निगम से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है, जिनके माध्यम से आरोपी गतिविधियों को कथित रूप से संरक्षण मिला। यह भी देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में संबंधित कार्यों को अनुमति दी गई और किस स्तर पर निर्णय लिए गए। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नगर निगम के स्तर पर सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या फिर नियमों की अनदेखी हुई। महापौर मालती राय को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में यह भी कहा जा रहा है कि बिना उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति के महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं होते। इन दावों के बीच जांच एजेंसियां फिलहाल तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ने की बात कह रही हैं। (शेष पेज 2 पर)

साय सरकार में छत्तीसगढ़ का खनन क्षेत्र : पारदर्शिता, तकनीक और नीति सुधारों से नई पहचान

-विजया पाटक

खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते कुछ वर्षों में खनन क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सोच, नीति-निर्माण और तकनीकी नवाचार में आए बुनियादी बदलावों को भी दर्शाती है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र को पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत विकास के सिद्धांतों से जोड़ते हुए एक नई दिशा दी है। इसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ आज देश के अग्रणी खनन राज्यों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। राज्य की खनिज संपदा लंबे समय से उसकी आर्थिक रीढ़ रही है, लेकिन साय सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि समग्र विकास के साधन के रूप में देखा गया। प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल व्यवस्था के जरिए खनिज प्रशासन को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का खनन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि देश के कुल खनिज उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह आँकड़े राज्य की खनन क्षमता और उसके कुशल प्रबंधन को दर्शाते हैं। राज्य गठन के समय खनिज राजस्व मात्र 429 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 14,592 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बीते 25 वर्षों में खनिज राजस्व में 34 गुना वृद्धि साय सरकार द्वारा अपनाई गई सुदृढ़ खनिज नीति, बेहतर निगरानी व्यवस्था और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है। (शेष पेज 2 पर)

गौवंश हत्या प्रकरण में एसआईटी की सख्ती, भोपाल की सत्ता के गलियारों में बढ़ी बेचैनी

(पेज 1 का शेष)

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का नाम आने से बढ़ी सियासी तपिश

इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि नगर निगम से जुड़े कई फैसलों में मंत्री स्तर की सहमति अहम भूमिका निभाती है। वहीं, भाजपा की ओर से अब तक इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को "नैतिकता और जवाबदेही" से जोड़ते हुए सरकार पर दबाव बना रहा है।

गौवंश हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति तेज

गौवंश से जुड़ा मामला होने के कारण यह प्रकरण केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन गया है। कई हिंदू संगठनों और सामाजिक समूहों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास के साथ भी धोखा होगा। इसी बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि खुद को गौ-संरक्षण का समर्थक बताने वाली सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब तक इस मामले में कोई सार्वजनिक रूप से बड़ा बयान या कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि, सरकार समर्थक पक्ष का तर्क है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

जांच का दायरा बढ़ने के संकेत, पुराने मामलों की भी हो सकती है पड़ताल

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, एसआईटी केवल वर्तमान मामले तक सीमित नहीं रह सकती। चर्चा है कि पूर्व में सामने आए कुछ अन्य आपराधिक नेटवर्क, जिनमें ड्रग्स सप्लाई और अवैध गतिविधियों के आरोप लगे थे, उनकी कड़ियों को भी खंगाला जा सकता है। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

विपक्ष का हमला, भाजपा की छवि पर असर का दावा

विपक्षी दलों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि यदि जांच में सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं, तो यह भाजपा और मध्यप्रदेश सरकार की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।

भाजपा का रुख: जांच पूरी होने दें

भाजपा के अंदरखाने से मिल रही जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व फिलहाल "वेट एंड वॉच" की नीति पर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी बचाने या फंसाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी तरह की राजनीतिक या संगठनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

राजनीतिक भविष्य पर असर की अटकलें

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच लंबी चलती है और नए नाम सामने आते हैं, तो इसका असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। राजधानी भोपाल की राजनीति में यह मामला आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल यह पूरा मामला जांच के अधीन है। आरोप, प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सच क्या है, यह एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण ने मध्यप्रदेश की राजनीति में बेचैनी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है।

साय सरकार में छत्तीसगढ़ का खनन क्षेत्र: पारदर्शिता, तकनीक और नीति सुधारों से नई पहचान

(पेज 1 का शेष)

निज विविधता और वैश्विक पहचान

छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट और टिन अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों के विश्वस्तरीय भंडार मौजूद हैं। हाल के वर्षों में किए गए नवीन अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता भी प्रमाणित हुई है। इन खनिजों का महत्व केवल औद्योगिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन खोजों के चलते छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल एक पारंपरिक खनन राज्य की नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य की बनती जा रही है।

खनिज नीलामी में पारदर्शी व्यवस्था

संशोधित खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत गठित खनिज नीलामी नियम 2015 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें 15 लौह अयस्क, 14 बाक्साइट, 18 चूना पत्थर और 13 क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 नए ब्लॉकों—2 चूना पत्थर, 1 लौह अयस्क, 1 स्वर्ण और 1 बेस मेटल ब्लॉक—की नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है। यह प्रक्रिया राज्य की निवेश-अनुकूल छवि को मजबूत करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष व्यवस्था का उदाहरण बन रही है।

वैज्ञानिक अन्वेषण की ओर बढ़ता राज्य

साय सरकार के कार्यकाल में खनन केवल दोहन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक

अनुसंधान और अन्वेषण को भी प्राथमिकता दी गई। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने आईआईटी मुंबई, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक सहयोग के लिए एमओयू संपादित किए हैं। इस साझेदारी से क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की खोज को वैज्ञानिक आधार मिला है, जिससे राज्य भविष्य की औद्योगिक जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

डीएमएफ व्यवस्था में बड़ा सुधार

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की गाइडलाइन-2024 के अनुरूप राज्य में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) नियम, 2025 अधिसूचित किए गए हैं। अब तक राज्य को 16,119 करोड़ रुपये का डीएमएफ अंशदान प्राप्त हुआ है। इस राशि से 1,05,653 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 74,454 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कौशल विकास और आजीविका से जुड़े ये कार्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वित्तीय स्वीकृति, निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किया गया है, जिससे जनभागीदारी और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो रही हैं।

खनिज प्रशासन का पूर्ण डिजिटलीकरण

खनिज विभाग द्वारा विकसित खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल ने राज्य के खनिज प्रशासन को पूर्णतः डिजिटल स्वरूप प्रदान किया है। यह प्रणाली सुरक्षित, बहुआयामी और उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जिससे खनन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांतों के अनुरूप रेत खदानों का आवंटन भी अब पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए एमएसटीसी के साथ एमओयू किया गया है। नई व्यवस्था में मानव हस्तक्षेप समाप्त कर प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाया गया है।

सतत और जिम्मेदार खनन की दिशा

गौण खनिज नियम, 2015 के अंतर्गत लागू की गई स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत खदानों का मूल्यांकन खनन प्रक्रिया, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और सतत विकास के मानकों पर किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 3 खदानों को 5-स्टार और 32 खदानों को 4-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। यह पहल यह दर्शाती है कि साय सरकार के लिए खनन केवल राजस्व का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलन बनाने की प्रक्रिया है।

विकास का नया मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार खनिज संपदा राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार है। साय सरकार ने नीतिगत सुधार, डिजिटल पारदर्शिता और सतत विकास के समन्वित प्रयासों से खनन प्रशासन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ में खनन क्षेत्र में आए ये परिवर्तन न केवल आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि सही नीति और मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति से संसाधनों का उपयोग जनहित में किया जा सकता है। साय सरकार के कार्यकाल में खनन क्षेत्र में हुआ यह बदलाव छत्तीसगढ़ को विकास की एक नई राह पर ले जाता दिखाई दे रहा है।

परीक्षा: अंक नहीं, आत्मविश्वास गढ़ने का समय

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

फरवरी की आहट के साथ ही देश के लाखों घरों में एक विशेष हलचल शुरू हो जाती है। यह वह समय है जब किताबों की गंध, कापियों के बिखरे पन्ने और घड़ियों की टिक-टिक पहले से कहीं अधिक तेज सुनाई देने लगती है। अक्सर हम कहते हैं कि परीक्षाओं का सीजन आ गया है, लेकिन गहराई से देखें तो जब फरवरी आता है, तो केवल परीक्षा नहीं आती—निर्णय भी आते हैं। यह निर्णय केवल इस बात के नहीं होते कि बच्चा अगली कक्षा में जाएगा या नहीं, बल्कि ये निर्णय होते हैं बच्चे के धैर्य, उसकी अनुशासन शक्ति और दबाव में काम करने की क्षमता के। यह समय केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के लिए भी धैर्य की एक कठिन परीक्षा का होता है। हमें सामूहिक रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि ये वार्षिक या बोर्ड परीक्षाएँ जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं हैं। ये तो महज एक माध्यम हैं व्यक्तित्व को निखारने का, अनुशासन सीखने का और अपनी सीमाओं को पहचानने का।

अंक बनाम योग्यता: एक बड़ा भ्रम

आज के दौर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अंक ही योग्यता का एकमात्र पैमाना हैं। समाज ने एक ऐसी धारणा बना ली है जहाँ 95% लाने वाला बच्चा ही 'योग्य' माना जाता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अंक केवल एक विशेष समय अंतराल में किए गए प्रदर्शन और याददाश्त का परिणाम होते हैं, वे किसी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता, उसकी रचनात्मकता और उसके चरित्र का प्रतिबिंब नहीं हो सकते। हमें बच्चों को यह समझाना होगा कि परीक्षाओं से आगे भी एक दुनिया है, और वही असली शिक्षा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्तियों में से कई शैक्षणिक रूप से औसत थे, लेकिन उनके पास हार न मानने का जज्बा और आत्मविश्वास था। सफलता की वास्तविक कहानी वह नहीं है जो केवल मार्कशीट पर सुनहरे अक्षरों में खत्म हो जाए, बल्कि वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको टूटने न दे। असली शिक्षा वह है जो आपको जीवन की परीक्षाओं के लिए तैयार करे, न कि केवल क्लासरूम की परीक्षा के लिए।

स्ट्रेस को स्ट्रैटेजी में बदलें

परीक्षा के दिनों में 'तनाव' एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, तनाव तब बोझ बनता है जब उसे 'डर' मान लिया जाए। जब हम परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो तनाव हमें पंगु बना देता है। लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही है कि तनाव को डर नहीं, रणनीति बनाना ही सफलता की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्यार्थी अपने तनाव को एक व्यवस्थित योजना या 'एक्शन प्लान' में ढाल देता है, वही तनाव एक 'पॉजिटिव स्ट्रेस' यानी ऊर्जा में बदल जाता है। याद रखें, हर बच्चा अनूठा है; उसकी सीखने की शैली और गति अलग है। जब हम एक बच्चे की तुलना दूसरे से करते हैं, तो हम उसकी मौलिकता का गला घोंट देते हैं। तुलना का बोझ बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर करता है, जबकि बड़ों का अटूट विश्वास उन्हें शिखर तक ले जाने की ताकत रखता है।

यह केवल बच्चों की परीक्षा नहीं: अभिभावकों की भूमिका

अक्सर परिवारों में माहौल ऐसा हो जाता है जैसे पूरा घर परीक्षा दे रहा हो, जिसका दबाव अनजाने में बच्चे पर ही आता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह समय केवल बच्चों का नहीं, अभिभावकों और शिक्षकों की भी कसौटी है। यह परीक्षा है माता-पिता के धैर्य की कि वे परिणाम की चिंता किए बिना बच्चे का साथ कैसे देते हैं। यह परीक्षा है शिक्षकों की संवेदनशीलता की कि वे कमजोर छात्र को कैसे प्रेरित करते हैं। आज के युवाओं को उपदेशों की नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सहायक माहौल की जरूरत है। उन्हें एक ऐसा सुरक्षित कोना चाहिए जहाँ गलती होने पर डाँट न मिले, बल्कि सुधार का रास्ता दिखाया जाए। जहाँ 'परिणाम' से पहले उनके द्वारा किए गए 'प्रयास' और रातों की गई 'मेहनत' को सम्मान मिले।

एक्शन प्लान: सफलता के लिए '6 मंत्र'

1. **यथार्थवादी योजना (Realistic Planning):**
हवा में महल बनाने के बजाय अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। विषयों की कठिनाई के आधार पर एक संतुलित टाइम-टेबल बनाएं। रोज के लक्ष्य इतने छोटे रखें कि वे पूरे हो सकें। अंतिम दिनों में कुछ भी नया पढ़ने के बजाय केवल पुराने नोट्स और की-पॉइंट्स के रिवीजन पर ध्यान दें।

2. **शारीरिक और मानसिक सेहत का संतुलन:**
अक्सर विद्यार्थी पढ़ाई के चक्कर में नींद और खाने से समझौता करते हैं। याद रखें, एक थका हुआ दिमाग जानकारी को संचित नहीं कर सकता। 7-8 घंटे की गहरी नींद और पौष्टिक भोजन उतना ही जरूरी है जितना कि गणित के सूत्र। हर 90 मिनट की गहन पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लें।

3. **डिजिटल डिटॉक्स और गहरी एकाग्रता:**
आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़े व्यवधान हैं। परीक्षा के दौरान इनसे पूर्ण दूरी बनाना ही श्रेयस्कर है। अपनी प्रगति को जाँचने के लिए मॉक टेस्ट का सहारा लें। इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के एक अवसर के रूप में देखें।

4. **सकारात्मक संवाद (Communication):**
माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ बच्चों के कंधों पर न डालें। बच्चों से निरंतर संवाद करें और उन्हें अहसास दिलाएं—"हमें तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है।" जब बच्चे को पता होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है।

5. **आत्म-प्रतिस्पर्धा की भावना:**
आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता कल के 'आप' से है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद करें और यह देखें कि आपने कल के मुकाबले आज कितना बेहतर सीखा है। कठिन विषयों से भागें नहीं, उनके लिए अलग से समय निकालें और शिक्षकों की मदद लेने में कभी संकोच न करें।

6. **दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव:**
परीक्षा को एक 'हौआ' या 'भय' न मानें, बल्कि इसे खुद को साबित करने का एक 'अवसर' समझें। खुद से कहें कि आप सक्षम हैं। यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक न भी रहे, तो भी संवाद के रास्ते खुले रखें। याद रखें, असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, यह जीवन का अंत नहीं है।

अंततः, परीक्षा हॉल में जाते समय यह याद रखें कि आपकी मार्कशीट के अंक यह तय नहीं कर सकते कि आप भविष्य में कितने सफल इंसान बनेंगे। वहाँ आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार और सच्ची जमा-पूंजी होगी। अपनी ओर से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रयास करें और परिणाम की चिंता भविष्य पर छोड़ दें। परीक्षा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, गहरी साँस लीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। यह समय खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने का है।

चिनकी-बोरास परियोजना:
नरसिंहपुर में किसानों का चक्का जाम, छूटे गांवों को शामिल करने की मांग पर 10 दिन से धरना जारी

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। प्रशासन द्वारा अब तक कोई सुनवाई न होने से नाराज किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यह कदम उठाया। उनकी मुख्य मांगों में चिनकी-बोरास सिंचाई परियोजना में शामिल न किए गए लगभग 40-42 गांवों को जोड़ना और क्षेत्र में पेयजल संकट का समाधान शामिल है। किसानों की कुल 9 से 14 सूत्रीय मांगें हैं। चक्का जाम के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। इससे पहले, किसानों ने तेंदुखेड़ा में एक विशाल रैली निकाली थी और एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था।

21 जनवरी से जारी धरना

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष यशवंत सिंह पटेल ने बताया कि 21 जनवरी से सैकड़ों किसान लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि परियोजना में 40-42 गांवों को शामिल न करने से किसान गंभीर संकट में हैं और क्षेत्र में पेयजल की भी भारी समस्या है। पटेल ने आरोप लगाया कि राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में शुक्रवार को किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर चक्का जाम कर दिया। यह प्रदर्शन चिनकी-बोरास बैराज सिंचाई परियोजना से छूटे गांवों को शामिल करने की मांग को लेकर किया गया। किसान बीते 10 दिनों से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे।

एक्शन मोड में MP कांग्रेस, राहुल गांधी की नाराजगी के बाद ताबड़तोड़ नियुक्ति

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। राहुल गांधी के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में तेजी देखने को मिल रही है। संगठनात्मक नियुक्तियों में लंबे समय से हो रही देरी को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तुरंत कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने 18 जिलों में संगठन महासचिव और 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। साथ ही सागर, छिंदवाड़ा और मऊगंज जिलों की जिला कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के जरिए उन नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, जो काफी समय से असंतोष जता रहे थे। इससे संगठन के भीतक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। सागर जिले में पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार पचौरी को जिला संगठन महासचिव बनाया गया है। राजकुमार पचौरी एक बार फिर जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में थे और उन्हें कमलनाथ खेमे का करीबी माना जाता है।

सुरेश कुमार दुबे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वहीं सिंगरौली ग्रामीण क्षेत्र में संकठा सिंह और सिंगरौली शहर में सुरेश कुमार दुबे को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की ये नियुक्तियां संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारियों को गति देने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं।

जल्द होगी बचे जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा

कांग्रेस संगठन ने पूर्व अधिकारी-कर्मचारी, अशासकीय विद्यालय सहित कुल 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही समाज समन्वय प्रकोष्ठ के अंतर्गत सात अलग-अलग समाजों के लिए समन्वयकों का चयन भी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव संजय कामले के अनुसार, बाकी बचे जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी जल्द की जाएगी।

शुक्रवार को दिल्ली में हुई थी बैठक

बता दें कि, शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल के साथ संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की और उन्हें जल्द ही संगठनात्मक पुनर्गठन की गतिविधियों को पूरा करने के निर्देश दिए।

सम्पादकीय

भारत–ईयू की 'मदर ऑफ़ ऑल डील्स' रणनीतिक साझेदारी की नई आधारशिला

भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आज "मदर ऑफ़ ऑल डील्स" कहा जा रहा है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि इस समझौते के व्यापक आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यदि यह समझौता सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो यह भारत और यूरोपीय संघ—दोनों के लिए अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक व्यापारिक उपलब्धि साबित हो सकता है।

यूरोपीय संघ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। दोनों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, तकनीक और नवाचार का बड़ा प्रवाह पहले से मौजूद है। ऐसे में यह समझौता केवल शुल्क घटाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपूर्ति शृंखलाओं, डिजिटल व्यापार, हरित अर्थव्यवस्था और टिकाऊ विकास जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की दिशा तय करेगा। यही कारण है कि इसे साधारण व्यापार समझौते के बजाय "मदर ऑफ़ ऑल डील्स" की संज्ञा दी जा रही है।

वैश्विक परिदृश्य में यह समझौता विशेष महत्व रखता है। दुनिया आज संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला में अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोपीय संघ जैसे लोकतांत्रिक और नियम-आधारित अर्थतंत्रों का एक-दूसरे के करीब आना वैश्विक व्यापार के लिए सकारात्मक संकेत है। यह समझौता बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में विश्वास को मजबूत कर सकता है।

भारत के लिए यह डील कई अवसर लेकर आती है। यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों—जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएँ, कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल—को बेहतर पहुँच मिल सकती है। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नयन को भी गति मिलेगी। साथ ही, यूरोपीय निवेश से भारत के विनिर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों को नया बल मिल सकता है।

दूसरी ओर, यूरोपीय संघ के लिए भारत एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। भारत की युवा आबादी, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढाँचे में हो रहे निवेश यूरोपीय कंपनियों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की यूरोप की रणनीति में भारत एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर सकता है।

हालाँकि यह रास्ता पूरी तरह सरल नहीं है। कृषि, बौद्धिक संपदा अधिकार, पर्यावरण मानक, श्रम कानून और डेटा संरक्षण जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे हैं। यूरोपीय संघ के सख्त पर्यावरण और कार्बन मानक भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बन सकते हैं, जबकि भारत अपनी नीतिगत स्वायत्तता और विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को लेकर सतर्क है। इसलिए इस "मदर ऑफ़ ऑल डील्स" की सफलता संतुलन और आपसी समझ पर निर्भर करेगी।

यह समझौता भारत के लिए एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है—यह उसे वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक मजबूत स्थान दिला सकता है। यदि भारत घरेलू सुधारों, गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान देता है, तो यह डील उसे वैश्विक विनिर्माण और सेवा केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है।

सियासी गहमागहमी

हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा में सब ठीक है?

प्रदेश भाजपा में इन दिनों सब "ठीक" चल रहा है। कम से कम बयानबाजी के स्तर पर। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन इतना अनुशासित हो गया है कि असंतोष भी फुसफुसाकर किया जा रहा है। बाहर से देखने पर पार्टी एकजुट, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरी दिखती है, लेकिन भीतर झाँकिए तो तस्वीर कुछ और ही रंग दिखाती है। कहीं टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है, तो कहीं पद न मिलने का मौन उपवास। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं "हम पार्टी के सिपाही हैं या केवल पोस्टर चिपकाने की मशीन?" मगर नेतृत्व आश्वस्त है कि सब संतुष्ट हैं, क्योंकि असंतुष्ट बोल नहीं रहे। और आजकल राजनीति में चुप्पी को ही सहमति मान लिया गया है। हेमंत खंडेलवाल संगठन को कसने में जुटे हैं, लेकिन कसावट कहीं-कहीं इतनी है कि संवाद की साँस लेने की जगह कम पड़ रही है। बैठकें हो रही हैं, प्रस्ताव पास हो रहे हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर चमक रही हैं बस जमीनी कार्यकर्ताओं के चेहरों की चमक थोड़ी फीकी है।

MP कांग्रेस में बदलाव की आहट संकेतों में छुपा सियासी संदेश

प्रदेश प्रभारी वेणुगोपाल द्वारा दिए गए हालिया संकेतों ने मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। भले ही शब्द संयमित हों, लेकिन संकेत साफ हैं पार्टी के शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। यह संकेत ऐसे समय में आए हैं, जब कांग्रेस लगातार चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक असंतोष से जूझती नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा आम रही है कि प्रदेश नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कमजोर पड़ा है। चुनावी हार, गुटबाजी और स्पष्ट रणनीति के अभाव ने पार्टी को भीतर से कमजोर किया है। ऐसे में वेणुगोपाल का बयान केवल एक औपचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि नेतृत्व को आत्ममंथन का संदेश माना जा रहा है। हालाँकि कांग्रेस में बदलाव की चर्चाएँ नई नहीं हैं, लेकिन इस बार फर्क यह है कि बात सीधे शीर्ष नेतृत्व तक जा पहुँची है। सवाल यह नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि बदलाव प्रतीकात्मक होगा या वास्तव में संगठन को नई दिशा देने वाला। अगर बदलाव केवल चेहरे बदलने तक सीमित रहा, तो इसका असर अल्पकालिक ही होगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है - वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफ़रत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की।

मगर राष्ट्रपिता ने हमें आज़ादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है - और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मुझे तोड़ लेना वनमाली! उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक

महान पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार तथा कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख और प्रभावशाली नाम हैं अजीत पवार

समता पाठक/जगत प्रवाह

अजीत अनंतराव पवार का विगत दिनों बारामती में प्लेन क्रेश में निधन हो गया। अजीत महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख और प्रभावशाली नाम हैं। वे एक अनुभवी राजनेता, कुशल प्रशासक और मजबूत निर्णय क्षमता वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने कई दशकों तक सक्रिय भूमिका निभाई है और राज्य के विकास, विशेषकर सिंचाई और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है।

अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुआ था। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे हैं। राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े अजीत पवार पर बचपन से ही राजनीति का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई भी महाराष्ट्र में ही पूरी की। पढ़ाई के साथ-साथ वे सामाजिक गतिविधियों और किसान मुद्दों में रुचि लेने लगे।

अजीत पवार का राजनीतिक जीवन औपचारिक रूप से 1991 में शुरू हुआ, जब वे पहली बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। यह क्षेत्र पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। अपनी पहली जीत के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई बार इसी क्षेत्र से विधायक चुने गए। जनता से उनका सीधा संवाद, स्थानीय समस्याओं की गहरी समझ और त्वरित निर्णय लेने की शैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है।

अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर कई बार नियुक्त हुए। पहली बार उन्होंने यह पद 2010 में संभाला। इसके अलावा वे वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, ऊर्जा मंत्री और योजना मंत्री जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। विशेष रूप से सिंचाई मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जल प्रबंधन और बांध परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया।

हालाँकि अजीत पवार का राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर उन पर कई बार आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को निर्दोष बताते हुए जनता के बीच सक्रिय रहना जारी रखा। उनकी छवि एक सख्त, अनुशासित और कभी-कभी आक्रामक नेता की रही है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि यही कठोरता उन्हें एक प्रभावी प्रशासक बनाती है।

2019 में अजीत पवार ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, जब उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालाँकि यह सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई और वे पुनः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लौट आए। इस घटना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना दिया।

अजीत पवार किसानों के मुद्दों, सूखा-प्रभावित क्षेत्रों और ग्रामीण विकास को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। बारामती और आसपास के क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों—जैसे सिंचाई परियोजनाएँ, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक विकास को स्थानीय जनता आज भी याद करती है। वे स्पष्टवादी नेता हैं और बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं।

व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अजीत पवार अपेक्षाकृत निजी जीवन जीना पसंद करते हैं। वे सादगीपूर्ण जीवनशैली और कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाते हैं। राजनीति के अलावा उन्हें प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं की बारीकियों में गहरी रुचि है। कुल मिलाकर, अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ हैं। समर्थक उन्हें विकास पुरुष मानते हैं, जबकि आलोचक उनके विवादों को लेकर प्रश्न उठाते हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने राज्य की राजनीति और प्रशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। उनका जीवन संघर्ष, सत्ता, विवाद और विकास—इन सभी का अनूठा मिश्रण है, जो उन्हें एक प्रभावशाली और चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व बनाता है।

सीएम धामी के नेतृत्व में जनहितैषी योजनाओं से लोग हो रहे लाभांवित

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न सेवा एवं जागरूकता अभियानों को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। सरकार की सक्रिय नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की जनहितकारी योजनाओं की स्वीकार्यता और प्रशासन की कार्यक्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यदि अब तक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुल 474 कैंपों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों के माध्यम से अब तक 3,77,358 नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना है। कैंपों के माध्यम से न केवल सेवाओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है, बल्कि आम जनता को सरकार से सीधे जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे अभियानों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाया जाए, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँच सके। यह उपलब्धि स्पष्ट करती है कि उत्तराखंड सरकार जनसेवा, पारदर्शिता और सुशासन के संकल्प पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

सिरपुर जिले को मिलेगी करोड़ों की सौगात

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। सिरपुर में आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। वे जिले में कुल 199 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपए की लागत की 99 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इनमें 40 करोड़ 88 लाख 2 हजार रुपए की लागत के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 158 करोड़ 40 लाख 57 हजार रुपए की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम अंतर्गत लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 98 लाख 80 हजार रुपए की लागत के 4 विकास कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपए की लागत के 19 विकास कार्य, आदिवासी विकास विभाग के 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रुपए की लागत का 1 विकास कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 17 करोड़ 95 लाख 86 हजार रुपए की लागत के 26 विकास कार्य तथा विद्युत विभाग के 13 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपए की लागत के 14 विकास कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार भूमिपूजन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 141 करोड़ 19 लाख 19 हजार रुपए की लागत से 22 विकास कार्य, जल संसाधन विभाग के 10 करोड़ 32 लाख 72 हजार रुपए की लागत से 3 विकास कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 2 करोड़ 18 लाख 93 हजार रुपए की लागत से 8 विकास कार्य तथा परिवहन विभाग के 4 करोड़ 69 लाख 73 हजार रुपए की लागत से 2 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा।

अवैध धर्मांतरण की समस्या से सख्ती से निपटने की जरूरत

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण कर ईसाई बने सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार अशिक्षित और गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर मतांतरित कराने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में शिवपुरी जिले के पटवारी और शिक्षकों द्वारा भील आदिवासियों का मतांतरण कराने का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पटवारी, दो सरकारी शिक्षिकाएं, एक शिक्षक और चर्च के पादरी को धर्म परिवर्तन में लिप्त पाए जाने पर अपराध दर्ज कर गिरफ्तार तो किया ही सभी को निलंबित भी कर दिया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। यह कार्यवाही ग्राम गुडाल डांग के सरपंच की शिकायत पर की गई। अवैध रूप से बनाई गई चर्च को भी जमींदोज कर दिया। गरीब भील आदिवासियों को 25-25 हजार रुपए का लालच देकर धर्मांतरित किया गया था। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3-5 के तहत पंजीबद्ध मामले में दोश सिद्ध होने पर 2 से लेकर 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मतांतरण की समस्या से निपटने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में हैं। इसके तहत दोहरा लाभ ले रहे मतांतरित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर रखने के प्रविधान रखे जाएंगे। दरअसल इस राज्य में अवैध मतांतरण ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। यह प्रविधान हो जाता है तो, जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के चलते मतांतरण की स्थिति में अनुसूचित जातियों (एससी) के लोग आरक्षण सहित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं, उसी तरह जनजातियों के लोग भी वंचित होने लग जाएंगे। जबकि ईसाई या मुस्लिम बने आदिवासी न केवल एसटी वर्ग का लाभ ले रहे हैं, बल्कि ईसाई के रूप में अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार इस कानूनी विसंगति को कठोर कानून बनाकर दूर करना चाहती है। इस प्रस्तावित विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने या कराने पर 10 वर्श तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। यह कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा।

एक आदिवासी नेता हुए हैं बाबा कार्तिक उरांव! वे हमेशा हिंदुत्व के पक्षधर रहे और धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण देने का विरोध करते रहे। बाबा कार्तिक उरांव तीन बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जीवन के अंतिम समय में वे नागरिक उड्डयन एवं संचार मंत्री थे। उरांव अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गुमला से मैट्रिक करने के बाद, वे ठक्कर बाप्पा के आश्रम में चले गए। उन्हीं की प्रेरणा से उरांव ने अभियांत्रिकी की कई डिग्रियां प्राप्त कीं। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होने नौ वर्ष बिताए। विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय ऊर्जा का प्रारूप उन्होंने ही बनाया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में उनकी भेंट जवाहरलाल नेहरू से हुई, उन्हीं के आग्रह पर वे भारत लौटे। यहाँ भारी अभियांत्रिकी निगम में काम करने लगे। 1962 में कांग्रेस के आग्रह पर, उन्होंने तत्कालीन बिहार के लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के डेविड मुंजनी से मात्र 17000 वोटों से हार गए। 1967 में फिर से उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा से चुनाव लड़ा और वे सांसद बने। 1977 की जनता लहर का अपवाद छोड़ दें, तो अपनी मृत्यु (1981) तक वे लोहरदगा का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते रहे। 8 दिसंबर 1981 को संसद भवन में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वे केंद्रीय उड्डयन और संचार मंत्री थे।

वनवासियों के ईसाई धर्मांतरण से वे क्षुब्ध थे। इसलिए 1967 में वे संसद में 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक-1967' लाए। इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने बहुत छानबीन की और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दीं। इनमें प्रमुख सिफारिश थी, कोई भी आदिवासी व्यक्ति, जिसने जनजाति आदिवासी मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा और न ही वह आदिवासियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का पात्र रह जाएगा। अर्थात धर्म परिवर्तन करने के पश्चात उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। संयुक्त समिति की सिफारिश के बावजूद, एक वर्ष तक इस विधेयक पर संसद में बहस ही नहीं हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशनरियों का जबरदस्त दबाव था कि इस विधेयक का विरोध करें। ईसाई मिशन के प्रभाव वाले 50 संसद सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पत्र दिया कि इस विधेयक को खारिज कर दें। कांग्रेस में रहते हुए इस मुहिम के विरोध में अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर कार्तिक उरांव ने 10 नवंबर को 322 लोकसभा सदस्य और 26 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों का एक पत्र इंदिरा गांधी को दिया, जिसमें यह जोर देकर कहा गया था की वे विधेयक की सिफारिशों का स्वीकार करें, क्योंकि यह तीन करोड़ वनवासियों के जीवन-मरण का प्रश्न हैं। किंतु ईसाई मिशनरियों के दबाव में इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं कार्तिक उरांव की प्रेरणा से इस विसंगति को दूर करने की तैयारी में है।

झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मध्यप्रदेश के दालसिंह बिस्सेन ने संसद में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का चलन लगातार बढ़ रहा हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद-342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद-341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिंदू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले 60 सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। इस बाबत रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट ने इस भेद को दूर करने की पैरवी की थी। लेकिन संविधान में संशोधन के बिना यह संभव नहीं था। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म या मत छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बन जाता है तो हिंदू होने के चलते उसके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने की अयोग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। लिहाजा उसे संरक्षण देना जरूरी नहीं है। इस लिहाज से उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी नहीं माना जाएगा। अतएव मतांतरण रोकने के लिए इस तरह का कानून अब छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश के लिए संसद के माध्यम से लाना अनिवार्य हो गया है।

महासागरों को निगल रहा प्लास्टिक का विष

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

महासागर जो पृथ्वी का जीवन आधार है आज प्लास्टिक के विषैले प्रदूषण से जूझ रहे हैं। हर साल अरबों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में समा जाता है, जो मछलियों, कछुओं और पक्षियों को निगलने पर मजबूर कर रहा है। समुद्र, जो हमारे ग्रह का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा है, जीवन की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय श्रोत है। लेकिन आज समुद्र एक नए संकट का सामना कर रहा है और वह संकट है प्लास्टिक प्रदूषण। यह समस्या न केवल समुद्री जीवन के लिए खतरनाक है बल्कि मानव स्वास्थ और आर्थिक स्थिति के लिए भी एक खतरा है। यदि बड़ी संख्या में प्लास्टिक के टुकड़े समुद्र में तैर रहे हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब समुद्र पानी का नहीं बल्कि प्लास्टिक का ही कहलाएगा। दुनिया में आज 40 प्रतिशत समुद्र किसी न किसी तरह से प्लास्टिक के चपेट में आ चुका है और माना जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रहा तो 2050 तक मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में होगा। समुद्र में प्लास्टिक से फैलता संकट आज मानवता और प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ जहां एक ओर जीवन सुविधाजनक हुआ, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग और बेतरतीब निपटान ने प्रकृति के सामने एक भीषण संकट खड़ा कर दिया। समुद्री सतहों, तटों और गहराइयों में जमा यह प्लास्टिक केवल समुद्री जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाश का कारण बन चुका है। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों व नालों से होते हुए समुद्रों तक पहुँचता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 192 देशों से निकला करीब 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है जो हर मिनट एक ट्रक प्लास्टिक के बराबर है। अंतराष्ट्रीय शोधों ने भी पुष्टि की है कि समुद्रों में पहुंचने वाला करीब 80 फीसदी कचरा जमीन पर ठोस कचरे के कुप्रबंधन से जुड़ा है, जो भूमि से जुड़े समुद्री मार्गों के जरिए समुद्र तल तक पहुंच रहा है। वहीं बाकी 20 फीसदी कचरा तटीय बस्तियों से समुद्रों में जा रहा है।

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें है- जैसे प्लेटें, बोतलें, बैग, फिशिंग नेट्स- जो उपयोग होने के बाद बिना किसी रोक टोक के समंदर तक पहुँच जाती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाली प्रजातियां, जैसे- कछुए, सील, मछलियां व पक्षी, अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझ कर निगल जाती हैं। नतीजा, प्लास्टिक उनके पेट में जमता जाता है और वे भूख या बीमारी के कारण तड़प-तड़प कर मर जाती हैं। प्लास्टिक से बने माइक्रो प्लास्टिक कण एक और बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये कण इतने छोटे आकार के होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन समुद्री जीव इनका आसानी से सेवन कर लेते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो ये माइक्रो प्लास्टिक अब समुद्री जैव-श्रृंखला के जरिये इंसानी खुराक तक भी पहुँचने लगे हैं, जो धीरे-धीरे हमारी सेहत पर भी गंभीर असर डालता है—कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, और जन्मजात विकार इसके कुछ उदाहरण हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्लास्टिक की उम्र हजारों साल होती है, यानी एक बार समुद्र में गया प्लास्टिक कभी – न कभी – समुद्री जीवन के लिए खतरा बन ही जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ जंतुओं व मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह असंतुलित कर रहा है। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे डेड जोन यानी निर्जीव क्षेत्र बन जाते हैं, जहाँ कोई भी जीवित प्राणी बच नहीं पाता। रिक्त स्थानों में जब ऑक्सिजन नहीं मिलती, तो पूरी खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ जाती है। प्लास्टिक कचरे को जलाने या लंबे समय तक सूर्य के ताप के नीचे रहने की स्थिति में, इसमें मौजूद रसायन व विषैले तत्व समुंदर के पानी में घुल जाते हैं, जिससे और अधिक विषाक्तता फैलती है। एक और चिंताजनक पहलू है "प्लास्टिक की चट्टानें" (Plastiglomerates) का बनना, जैसा कि हाल में भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर देखा गया। ये चट्टानें प्लास्टिक और रेत के मेल से बनती हैं, जिनमें सैकड़ों खतरनाक रसायन होते हैं। शोधों के अनुसार, समुद्र की गहराइयों में अब लगभग एक करोड़ दस लाख टन प्लास्टिक जमा हो चुका है। इस संकट का समाधान सरल नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग बंद करें, सिंगल-यूज प्लास्टिक के विकल्प चुनें, और प्लास्टिक कचरे के जिम्मेदार निस्तारण का प्रण लें। सरकार व समाज को मिलकर कानून और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के ठोस प्रयास करने होंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश के प्रयास काफी नहीं, पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस महासंकट का हल ढूंढना होगा। समुद्र हमारे पृथ्वी का फेफड़ा हैं। अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति स्वयं हमसे ऐसी कीमत चुकाएगी जिसकी भरपाई कभी न हो पाएगी।

श्री विद्यासागरजी महामुनिराज के चरणों की शोभायात्रा निकाली

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह, विदिशा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागरजी महामुनिराज का दितीय समाधि गुरु चरणों की पूजा निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभवसागर महाराज, मुनि श्री निस्सीम सागर महाराज, मुनिश्री संस्कार सागर महाराज के संघ सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके पूर्व 26 जनवरी को संपूर्ण विदिशा नगरी में चरणों की शोभायात्रा निकाली गई। उक्त चरणों को रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा के रुप में रखा गया एवं उसके पीछे निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभवसागर महाराज स संघ सानिध्य में चल रहे थे। आगे आगे गजराज पर संजय मामा धर्मध्वजा लेकर चल रहे थे। यह विशाल शोभायात्रा श्री शांतिनाथ दि. जैन मंदिर माधवगंज से प्रारंभ हुई जो कि पुराने हास्पिटल रोड़ से होती हुई संयम कीर्ति स्तंभ से होती हुई नीमताल चौराहे से तिलक चौक, निकासा रोड़ होती हुई किरी मौहल्ला में महावीर जिनालय से होती हुई माधवगंज स्टेशन जैन मंदिर पर समापन हुआ। संपूर्ण रास्ते में स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान के सामने रांगोली बनाकर गुरुदेव के चरणो पर श्रीफल अर्पित कर आरती उतारी एवं मुनिसंघ का पड़गाहन कर पाद प्रछालन कर अपने आपको धन्य महसूस किया। रास्ते भर गुरुदेव की जयजयकार करते हुये भक्तों ने भक्तीरूपी गीतों से सभी का मन मोह लिया। प्रवक्ता अविनाश जैन विद्यावाणी ने बताया आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागरजी महामुनिराज का द्वितीय समाधि दिवस जो कि माघशुक्ल नवमी तिथी जो कि 27 जनवरी मंगलवार को हैं, आपकी समाधि माघशुक्ल नवमी 18 फरबरी2024 को भगवान श्री चंद्रप्रभु के अतिशय क्षेत्र डोंगरगढ़ चंद्रगिरि (छत्तीसगढ़) से इस नश्वर शरीर को छोड़ा था।

कार्यालय नगरपालिका परिषद विदिशा म0प्र0

क्रमांक......../नामा.शाखा/2026 302 विदिशा दिनांक 21/1/26

इस्तहार उजरदारी–सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न भवन/प्लाट/दुकान के स्वामियों द्वारा नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण निम्न है।

क्र	आवेदक का नाम एंव पिता का नाम व पता	नामान्तरण हेतु भवन/भूखण्ड का विवरण	प्र.क्र
1	श्रीमति मोहन बाई पत्नी श्री रमेश कुमार साहू नि विदिशा	भूखण्ड 1930 वर्गफिट जतरापुरा वार्ड 02 विदिशा	157x7 2026
2	श्रीमति मोहन बाई पत्नी श्री रमेश कुमार साहू नि विदिशा	भूखण्ड 1780 वर्गफिट जतरापुरा वार्ड 02 विदिशा	158x7 2026
3	श्रीमति मोहन बाई पत्नी श्री रमेश कुमार साहू नि विदिशा	भूखण्ड 1000 वर्गफिट जतरापुरा वार्ड 02 विदिशा	159x7 2026
4	श्रीमति मोहन बाई पत्नी श्री रमेश कुमार साहू नि विदिशा	भूखण्ड 1000 वर्गफिट जतरापुरा वार्ड 02 विदिशा	160x7 2026
5	श्री जगत सिंह विश्वकर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा नि विदिशा	भूखण्ड 900 वर्गफिट अयोध्यापुरी कालोनी फेस 1 टीलाखेडी वार्ड 39 विदिशा	161x7 2026
6	श्री रामकुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल नि विदिशा	भूखण्ड 900 वर्गफिट सांची रोड वार्ड 11 विदिशा	162x7 2026
7	श्रीमति अन्नपूर्णा सर्राफ उर्फ दीपशिखा पत्नी श्री राजेश कुमार नि विदिशा	भवन वर्गफिट बड़ा बाजार वार्ड क्र 24 विदिशा	163x7 2026
8	भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजेश कुमार शर्मा नि विदिशा	भूखण्ड 1000 वर्गफिट रायपुरा नई बस्ती के पास वार्ड 10 विदिशा	164x7 2026
9	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण सर्राफ नि विदिशा	भवन वर्गफिट बड़ा बाजार वार्ड क्र 24 विदिशा	165x7 2026
10	श्री संतोष सोलंकी पुत्र श्री महाराज सिंह ,श्री सुशीला बाई सोलंकी पत्नी श्री कल्याण सिंह नि विदिशा	भवन 450 वर्गफिट नीमताल वार्ड क्र 24 विदिशा	166x7 2026
11	श्रीमति रुचि तिवारी पुत्री सुरेन्द्र तिवारी पत्नी श्री गौरव शर्मा नि विदिशा	भूखण्ड 1549.44 वर्गफिट गणपत कालोनी वार्ड 39 विदिशा	167x7 2026
12	श्रीमति संध्या सिंघई पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघई नि विदिशा	भूखण्ड 1840 वर्गफिट विद्या विहार कालोनी वार्ड 35 विदिशा	168x7 2026
13	श्री शुभम बाबरिया पुत्र श्री नारायण बाबरिया नि विदिशा	भूखण्ड 800 वर्गफिट इन्द्रप्रस्थ कालोनी वार्ड 35 विदिशा	169x7 2026

अतः उक्त भवन/प्लाट/...पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के अन्दर कार्यालीन समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। अन्यथा अवधि समाप्त होने के उपरांत नगरपालिका के रजिस्टर में उक्त नाम दर्ज कर लिया जावेगा। बाद में कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

For मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद विदिशा

पृ. क्रमांक 303 /नामा.शाखा/2026 विदिशा दिनांक 21/1/26

1–संवाददाता जगत प्रवाह ....दैनिक समाचार पत्र विदिशा की ओर इस्तहार उजदारी की सूचना 01 दिन प्रकाशन कर प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित रूपये 2500/– का देयक 02 प्रतियों में भुगतानार्थ प्रस्तुत करें

2–संबधित भवन/प्लाट/खण्डर क.............................जिसकी की नामान्तरण होना है पर एक प्रति चस्पा हेतु ।

3–नगरपालिका कार्यालय/कलेक्टर कार्यालय/तहसील कार्यालय/विदिशा के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चस्पा करे।

For मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद विदिशा

मोदी संग बढ़त हे छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

पीएम आवास योजना
26 लाख से अधिक परिवारों को पक्की छत देने वाले

महतारी वंदन योजना
70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले

पीएम किसान सम्मान निधि
26 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाले

तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹5500 मानक बोरा
13 लाख संग्राहक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले

उद्यम क्रांति योजना
युवाओं को स्वरोज़गार के लिये **50% सब्सिडी** पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाले

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने वाले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
37 लाख महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाले

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना
37 हजार से अधिक राम भक्तों को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराने वाले

छत्तीसगढ़ में शांति, विश्वास और विकास का मार्ग हो रहा प्रशस्त

R.O. No. : 13643/ 1

श्री विष्णु देव साय
मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)